

आतंकवाद एक वैश्विक समस्या : तालिबान के संदर्भ में

मनोज भाटी

शोधार्थी , माधव विश्वविद्यालय , आबूरोड ,सिरोही , राजस्थान

सारांश

वर्तमान समय में आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है। इसका अर्थ है हिंसा एवं भय के द्वारा लोगों में आतंक पैदा करना और इसके द्वारा अपने राजनीतिक, धार्मिक एवं वैचारिक उद्देश्यों को मान्यता दिलवाना। इसे एक संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके अंतर्गत बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है , सामाजिक शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डाला जाता है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। बम धमाकों ,आत्मघाती हमलों ,गोलीबारी ,अपहरण जैसे कृत्यों के द्वारा आतंकवादी संगठन समाज में डर का माहौल बनाकर अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास करते हैं। आज इस समस्या से विश्व का लगभग हर एक देश किसी न किसी रूप से जूझ रहा है। आतंकवाद के कारणों का यदि अध्ययन किया जाए तो कुछ कारण निकलकर सामने आते हैं जैसे कि अशिक्षा ,बेरोज़गारी ,गरीबी ,राजनीतिक असंतोष ,विदेशी हस्तक्षेप इत्यादि लेकिन एक ऐसा कारण है जो मुख्यतया आतंकवाद की नींव माना जा सकता है वह है “धार्मिक कट्टरता”। यही धार्मिक कट्टरता आगे बढ़कर इस्लामिक आतंकवाद को जन्म देती है। इस शोध पत्र में इस्लामिक आतंकवाद की पृष्ठभूमि में प्रमुख वैश्विक आतंकी संगठनों का परिचय एवं विशेष रूप से तालिबान के उद्भव विकास एवं प्रभाव का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। इस्लामिक आतंकवाद को यदि परिभाषित किया जाए तो यह एक ऐसी चरमपंथी विचारधारा है जिसमें कुछ समूह इस्लाम की कट्टर व्याख्याओं को आधार बनाकर हिंसक एवं आतंकवादी गतिविधियों को सही ठहराते हैं। ऐसे ही कई वैश्विक संगठनों में एक प्रमुख संगठन है तालिबान जिसके कारण लंबे अरसे तक अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिरता एवं भय का माहौल बना रहा।

मुख्य शब्द : आतंकवाद , तालिबान,अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ,मानवाधिकार ,शांतिपूर्ण सह अस्तित्व

परिचय : 1990 के दशक में तालिबान अस्तित्व में आया। 1996 से 2001 तक अफ़ग़ानिस्तान के शासन की बागडोर तालिबान के हाथ में ही थी। इसके बाद अमेरिका और नाटो सेनाओं ने वहाँ इसे उखाड़ फेंका लेकिन इसके बाद 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान पुनः सत्ता पर

काबिज़ हो गया। तालिबान ने अपने शासन के दौरान शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों एवं मानवाधिकारों को रौंदकर रख दिया। यह शोध पत्र यह स्पष्ट करता है कि इस्लामिक आतंकवाद किसी एक देश विशेष की समस्या नहीं है वरन् यह पूरे वैश्विक समुदाय के खतरा है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर शांति, विकास एवं मानवीय मूल्यों का घोर उल्लंघन करता हुआ आ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जैसे की शिक्षा का प्रसार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं समर्थन तथा आतंकवादी समूहों की वित्तीय एवं वैचारिक जड़ों की समाप्ति।

मूल आलेख :

विश्व में आतंकवाद की समस्या एक गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दा है। यह समस्या मानव जाति की सबसे बड़ी शत्रु है। यह एक ओर जहाँ लोगों की जान लेती है वहीं दूसरी ओर सामाजिक शांति, विकास एवं सुरक्षा को भी बाधा पहुँचाती है। पूरे विश्व में आतंकवाद नाम की बीमारी के फैलने के बाद से ही कई बार इसे इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है। इस्लामिक आतंकवाद को यदि हम परिभाषित करना चाहे तो इस्लामिक आतंकवाद में वे आतंकवादी गतिविधियाँ एवं कार्य सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनके पीछे अपने आप को मुसलमान कहने वाले चरमपंथी होते हैं। ये चरमपंथी अपने विभिन्न राजनीतिक एवं वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आतंकवाद को इस्लाम से जोड़े जाने की इस सोच को एक पक्ष उचित मानता है वहीं दूसरी ओर एक दूसरा पक्ष इसकी आलोचना करता रहा है। इसी बात पर एक बड़े लंबे समय से बहस की जाती रही है कि आतंकवाद को किसी विशेष धर्म के साथ जोड़ा जाना क्या उचित है? ऐसा किया जाना बिल्कुल ग़लत है और कुछ राह भटके लोगों की वजह से किसी एक धर्म को कटघरे में खड़ा करना सरासर ग़लत है। कोई भी धर्म हिंसा करने को सही नहीं बताता है लेकिन जब इस्लाम की आड़ में कुछ मुट्ठीभर लोग आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तब समाज का एक बहुत बड़ा पक्ष इस्लाम को दोषी ठहराता हुआ नज़र आता है। इस्लामिक आतंकवाद के कारण सबसे अधिक घटनाएँ एवं मौतें अफ़ग़ानिस्तान, भारत, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, यमन, माली और सोमालिया में हुई हैं। ग्लोबल टेररिज़्म इंडेक्स 2016 के अनुसार, 2015 में इस्लामिक आतंकवाद से होने वाली सभी मौतों के 74 प्रतिशत के लिए जो इस्लामिक चरमपंथी समूह जिम्मेदार थे वे हैं - ISIS (आई एस आई एस), बोको हराम, तालिबान एवं अलकायदा। सन 2000 के बाद से ही वैश्विक स्तर पर इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन घटनाओं ने न केवल एशिया एवं अफ़्रीका के मुस्लिम बहुल राज्यों को ही प्रभावित किया बल्कि इसका प्रभाव ग़ैर मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों जैसे कि फ़्रान्स, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम, रूस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, श्रीलंका, चीन, भारत एवं फ़िलिपींस आदि पर

भी पड़ रहा है। इस्लामी चरमपंथी समूहों के द्वारा नागरिकों पर किए जाने वाले हमलों का औचित्य इस्लामी पवित्र पुस्तकों (कुरान और हदीस साहित्य) की चरम व्याख्याओं से आता है। विश्व में कई छोटे बड़े आतंकवादी संगठन हैं लेकिन कुछ आतंकी समूह ऐसे हैं जो तक्ररीबन पूरी वैश्विक आबादी के लिए खतरा बने हुए हैं। इन इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को विश्व की तक्ररीबन सभी देशों ने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। ऐसे कुछ प्रमुख संगठन है :-

1. इस्लामिक स्टेट (ISIS) :

इस्लामिक स्टेट जिसे ISIS के नाम से भी जाना जाता है , दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक है। इस आतंकी संगठन ने उत्तरी इराक और पश्चिमी सीरिया पर कब्ज़ा कर वहाँ अपनी सरकार बना ली है। इस बर्बर संगठन का गठन अबू बक्र अल बगदादी ने किया था। इस आतंकवादी संगठन में दुनिया भर के लड़ाके शामिल हैं।

2. अलकायदा :

दुनिया भर के बर्बर आतंकवादी संगठनों में अलकायदा भी ISIS की तरह ही शीर्ष पर विद्यमान है। इसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन ने 1989 में की थी। अमेरिका में 9/11 का हमला अलकायदा ने किया था जिसका नेतृत्व ओसामा बिन लादेन ने किया। इस हमले के बाद से ही अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई शुरू की और मई 2012 में लादेन को मार गिराया। अब इस संगठन का नेतृत्व इसका नेटवर्क फिर से मजबूत करने में लगा है।

3. तहरीक - ए - तालिबान पाकिस्तान :

इस आतंकी संगठन ने अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर मौजूद आदिवासी क्षेत्र को अपना ठिकाना बना रखा है। यह कई छोटे बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठनों से मिलकर बना है। इसकी स्थापना पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी बैतुल्लाह महसूद ने की थी जिसकी अगस्त 2009 को मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी तालिबान के नाम से कुख्यात यह संगठन अक्सर पाकिस्तानी राज्यों को ही अपना निशाना बनाता रहा है। दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल पर हमला कर कई मासूम बच्चों की जान लेने के पीछे भी यही संगठन ज़िम्मेदार है।

4. बोको हराम : यह नाइजीरिया का एक प्रमुख इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो उत्तरी पूर्वी नाइजीरिया में मुख्यतया काम करता है। बोको हरम का शाब्दिक अर्थ है "पश्चिमी शिक्षा पाप है।" 2002 में मोहम्मद यूसुफ द्वारा स्थापित यह संगठन अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है। विश्व की

नज़रों में यह संगठन तब आया जब इसने अप्रैल 2014 में नाइजीरिया के एक स्कूल से 250 छात्रों का अपहरण कर लिया था ।

5. हमास :

यह फिलिस्तीन का एक सामाजिक - राजनीतिक आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में की गई थी ।हमास का अर्थ है “ हरकत उल मुकवामा अल इस्लामिया “ । इस संगठन को आत्मघाती हमलों के लिए जाना जाता है । इसका ज़िहाद इज़राइल के खिलाफ है और इसका उद्देश्य फिलिस्तीन की आज़ादी को सुरक्षित रखना है मुख्यतया इज़राइल से । इस संगठन को इज़राइल के विरुद्ध अपने अभियान में हिज़्बुल्लाह का समर्थन भी हासिल है ।

6.अल नुस्त्रा फ्रंट :

यह संगठन लेबनान और सीरिया में अलकायदा की एक शाखा के रूप में काम करता है । अल नुस्त्रा फ्रंट अर्थात जमात अल नुस्त्रा का अरबी भाषा में अर्थ है “अल शाम के लोगों के समर्थन में मोर्चा “ । सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन एवं बशर अल - असद शासन के खिलाफ सीरियाई नागरिक युद्ध में सम्मिलित अबू मोहम्मद अल जुलानी इस संगठन का प्रमुख था ।

7. हिज़्बुल्लाह :

1982 के लेबनानी गृह युद्ध के बाद यह संगठन ईरान और सीरिया के समर्थन से उभरा एक प्रमुख लेबनानी आतंकवादी संगठन है । इस संगठन को सुन्नी अरब देशों एवं इज़रायल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है।

8. तालिबान :

तालिबान पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है छात्र । तालिबान विश्व के चुनिंदा आतंकवादी समूहों में से एक है जिसने किसी देश पर शासन किया हो ।तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता की बागडोर सँभाली । मुल्ला मोहम्मद उमर द्वारा स्थापित इस संगठन ने अफ़ग़ानिस्तान में शरीयत और इस्लामी क़ानून लागू कर उसे सदियों पीछे धकेल दिया । अलकायदा समर्थित इस समूह को अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान से उखाड़ फेंका था लेकिन 2021 में अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एक बार फिर तालिबान ने वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली है।

तालिबान का परिचय

अफ़ग़ानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ। तालिबान पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरवाद से पूरी तरह से प्रेरित हों। कहा जाता है कि 1990 के दशक में जब अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी तो कई गुटों में झड़प हुई। इस झड़प ने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया। इसके बाद तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के कंधार शहर को अपना पहला केंद्र बनाया। अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन जो कभी सोवियत संघ के हाथ में थी जिसे 1989 में मुजाहिदीन ने बाहर का रास्ता दिखाया था, इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। उमर ने ही आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। पाकिस्तान हमेशा इस बात से इंकार करता रहा है कि तालिबान के उदय के पीछे उसका हाथ रहा है लेकिन यह सभी जानते हैं कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा ली थी। साल 1994 में जब मुल्ला मोहम्मद उमर ने कंधार में तालिबान को बनाया तब उसके पास 50 समर्थक थे जो सोवियत काल के बाद गृह युद्ध के दौरान अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार में बर्बाद होते अफ़ग़ानिस्तान को सँवारना चाहते थे। धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैलने लगा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान से लगे हेरात पर कब्ज़ा किया और फिर अगले साल 1996 के दौरान राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया। रब्बानी अफ़ग़ानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने सोवियत ताक़त का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90 प्रतिशत अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा था।

शुरुआत में अफ़ग़ानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया। उस समय चल रहे गृह युद्ध से लोग बुरी तरह प्रभावित थे और सुरक्षा के लिए एक बड़ा मसला था। साथ ही तालिबान ने भ्रष्टाचार से लड़ने और अफगानों की सुरक्षा करने का वादा भी किया। ऐसे में इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान की शकल में देखा गया। तालिबान ने तेज़ी से अपना प्रभाव बढ़ाया और शरिया क़ानून को बढ़ावा दिया। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। वो इस्लामिक क़ानून के मुताबिक सजा देने लगे जैसे हत्या और व्यभिचार के लिए सार्वजनिक फाँसी और चोरी के लिए अंग भंग करना। पुरुषों के लिए दाढ़ी बढ़ाना और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तालिबान ने TV, संगीत और सिनेमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया और दस साल या उससे ज़्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पाबंदी लगा दी।

दुनिया की नज़रों में तालिबान आया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद। जब अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन सितंबर 2001 के आतंकी हमले की प्लानिंग कर

रहा था तब तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा को सौंपने के लिए कहा लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया। उमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। यहाँ उन्होंने फिर से अफ़ग़ानिस्तान लौटने की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका अब पूरी तरह से अफ़ग़ानिस्तान की बागडोर अपने हाथ में ले चुका था। अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका का प्रभुत्व अगले 20 वर्षों तक कायम रहा। फ़रवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान ने ऐतिहासिक समझौता किया इसमें अमेरिकी सेना को 14 महीने में अफ़ग़ानिस्तान छोड़ना था। साथ ही तालिबान को भी अल कायदा जैसे संगठनों को पनाह देना ख़त्म करना था। इसी बीच तालिबान और अफ़ग़ानिस्तान सरकार के बीच जंग ख़त्म करने के लिए बातचीत होनी थी जिसका ठोस परिणाम नहीं निकल सका। तालिबान आतंकियों से संपर्क ख़त्म करने का वादा भी नहीं निभा सका। अब अमेरिकी सेना के देश छोड़ने के साथ ही तालिबान की क्रूरता अपने चरम पर पहुँचने लगी। पत्रकारों, अधिकारियों एवं एक्टिविस्ट को टारगेट करके मारा जा रहा था। BBC की रिपोर्ट में NATO के आंकलन के हवाले से दावा किया गया कि तालिबान आज पहले से ज़्यादा मज़बूत होकर उभरा है। अब इसमें 85,000 लड़के शामिल हैं। करीब बीस साल तक जंग के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी अपने हाथ वहाँ से खींच लिए और तालिबान इसे अपनी जीत समझते हुए ताबड़ तोड़ हिंसा मचाते हुए आगे बढ़ता रहा।

अमेरिकी सेनाओं के अफ़ग़ानिस्तान छोड़ते ही तालिबान ने बड़ी तेज़ी से वापसी की और अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर फिर से क़ाबिज़ हो गया।

युद्ध के बाद अफ़ग़ानिस्तान की समस्याएं :

जैसे ही अमेरिकी सेना के साथ तालिबान का टकराव समाप्त हुआ और अमेरिकी वापसी का पूरा होना निकट आ गया एक मज़बूत तालिबान ने मई - जून 2021 में तेज़ी से अफ़ग़ानिस्तान पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अगस्त 2021 के मध्य तक केंद्र सरकार का पतन हो गया था और तालिबान ने काबुल सहित लगभग पूरे देश पर क़ब्ज़ा कर लिया था। अमेरिका - तालिबान टकराव की समाप्ति के पश्चात अफ़ग़ानिस्तान अब दिन प्रतिदिन नई समस्याओं से जूझ रहा था जोकि निम्नांकित हैं :-

1. आर्थिक और मानवीय संकट –

2022 में अफ़ग़ानिस्तान का मानवीय संकट बिगड़ गया , जिसका मुख्य कारण तालिबान के अधिग्रहण के बाद देश का स्थाई आर्थिक पतन था । 90 प्रतिशत से अधिक आबादी पूरे वर्ष खाद्य असुरक्षित रही , जिसमें करोड़ों लोगों को रोज़ाना भोजन छोड़ने या पूरे दिन बिना खाए रहने को मजबूर होना पड़ा । लगातार कुपोषण से बच्चों में भुखमरी से होने वाली मौतों और दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है ।

2. महिलाओं और लड़कियों के अधिकार –

सत्ता संभालने के बाद से तालिबान ने नियमों और नीतियों की एक लंबी और बढ़ती हुई सूची लागू की है जो महिलाओं और लड़कियों को उनके मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकती है । जिसमें अभिव्यक्ति ,आंदोलन ,काम और शिक्षा शामिल हैं जो जीवन , आजीविका सहित उनके सभी अधिकारों को प्रभावित करती है ।

3. हत्याएं ,यातनाएं और युद्ध अपराध –

तालिबान बलों ने बदला लेने के लिए हत्याएं की हैं और पूर्व सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बल के कर्मियों को ज़बरन गायब कर दिया है । उन्होंने संक्षेप में उन लोगों को भी मार डाला है जिनके बारे में उनका दावा है कि वे खुरासान प्रांत (ISKP) के इस्लामिक राज्य के सदस्य हैं ।

4. इस्लामिक स्टेट ऑफ़ खुरासान प्रोविंस (ISKP) द्वारा हमले –

ISKP ने सन 2002 में हज़ारों के खिलाफ कई बम विस्फोटों और सशस्त्र हमलों की ज़िम्मेदारी ली ,जिसमें कम से कम 700 लोग मारे गए और घायल हुए।

5. मीडिया ,भाषण की स्वतंत्रता -

तालिबान अधिकारियों ने काबुल और प्रांतों में अफ़ग़ान मीडिया के खिलाफ़ व्यापक सेंसरशिप और हिंसा की । अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से सैकड़ों मीडिया आउटलेट बंद कर दिए गए और पूरे अफ़ग़ानिस्तान में अनुमानित 80 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने अपनी नौकरी खो दी या पेशा छोड़ दिया । इस प्रकार अफ़ग़ानिस्तान के सामने और कई चुनौतियां हैं जिनका सामना उसे करना है। इस शोध पत्र में मेरे द्वारा तालिबान समस्या के परिप्रेक्ष्य में विवेचनात्मक विश्लेषण करने का एक सूक्ष्म एवम् ईमानदार प्रयास किया गया है।

प्रमुख घटनाक्रम :

जब तालिबान सत्ता पर काबिज़ था तब मात्र तीन देशों पाकिस्तान , संयुक्त अरब अमीरात एवं सऊदी अरब ने उसे मान्यता दी और ऐसा भी माना जाता रहा है कि तालिबान को पाकिस्तान एवं सऊदी अरब से धन भी मिल रहा था ।

*अमेरिका पर किए गए 9/11 हमले के बाद तालिबान ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा ।

*अमेरिका पर किए गए 9/11 के दोषी ओसामा बिन लादेन एवं आतंकी संगठन अलकायदा को शरण देने का आरोप भी तालिबान पर लगाया गया ।

*अमेरिका 2001 में अफ़ग़ानिस्तान में आया , जिसे आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी गई ।

*अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य अलकायदा को नियंत्रित करना था जिससे आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

*अक्टूबर 2001 में अमेरिका एवं नाटो देशों की सेनाओं के गठबंधन द्वारा तालिबान को शासन से अलग कर दिया गया ।*आधिकारिक रूप से पाकिस्तान ने 9/11 की घटना के बाद तालिबान से अपने सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे लेकिन ऐसा भी माना जाता रहा है कि तालिबान के कई प्रमुख नेता पाकिस्तान भाग गए और वहीं रहकर उन्होंने संगठन को नियंत्रित भी किया ।

*दिसंबर 2001 में हामिद करज़ई के नेतृत्व में अफ़ग़ानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया ।

*कई वर्षों की लड़ाइयों एवं संघर्ष के पश्चात अफ़ग़ानिस्तान धीरे धीरे अविकसिता को पीछे छोड़ पुनर्निर्माण करने लगा ।

* हालाँकि इसी दौरान तालिबानी नेता मुल्ला उमर ने तालिबान का पुनर्गठन कर अफ़ग़ानिस्तान की सरकार के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। इसमें अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध आत्मघाती हमले ,घात लगाकर हमला करना एवं हत्याएं इत्यादि सम्मिलित हैं।

*2000 के दशक में के उत्तरार्ध में नागरिकों की हत्याओं में भी तेज़ी आयी ।

*20 साल बाद जब अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने की बात कर रहा था तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने मार्च 2021 में अफ़ग़ानिस्तान शांति समझौते के लिए एक मसौदा तैयार किया। इसके अंतर्गत तालिबान के साथ एक सरकार के गठन की परिकल्पना की गई जिसमें अफ़ग़ानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को रोकने के प्रावधान सम्मिलित हैं।

*अगस्त 2021 में तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था । अफ़ग़ानिस्तान में तेज़ी से सरकार गिरने एवं पुनः तालिबान के कब्ज़े से अफ़ग़ानिस्तान में दहशत का माहौल था और इसी दौरान कई लोग देश छोड़कर चले गए ।

तालिबान के साथ भारत के संबंध : भारत एवं तालिबान के संबंध जटिल एवं बदलते रहे हैं । भारत ने सत्ता में रहने के दौरान कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी । 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को अपहृत करके कंधार में उतारा गया और यह संदेह था इस पूरे घटनाक्रम में तालिबान ने अपहरणकर्ताओं का समर्थन किया था ।

तालिबान एवं भारत के संबंधों का संक्षिप्त विवरण:

1990 का दशक :

भारत ने कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी और तालिबान शासन के दौरान अफ़ग़ानिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया ।

2001:

9/11 हमलों के बाद भारत ने अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन दिया और तालिबान को उखाड़ने में मदद की ।

2001-2021 :

भारत ने तालिबान के साथ सीधे संबंध तो स्थापित नहीं किए लेकिन अफ़ग़ानिस्तान सरकार के साथ मिलकर अफ़ग़ानिस्तान में विकास परियोजनाओं और सहायता के माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

2021 :

तालिबान ने अमेरिकी सेनाओं की वापसी के साथ ही पुनः अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया । भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया और अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल लिया ।

2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तालिबान के बीच शांति वार्ता की पृष्ठभूमि के बाद तालिबान ने भारत के साथ सकारात्मक संबंधों की माँग की और कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और वह अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । वर्तमान में भारत और तालिबान

के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है और तालिबान शासन के अंतरगत मानवाधिकार और लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

निष्कर्ष एवं महत्व :

एक शोध पत्र का उद्देश्य पाठक को समस्या से परिचित कराना , किसी विषय विशेष के अध्ययन की आवश्यकता को महत्व देना होता है। साथ ही साथ एक शोध पत्र किसी समस्या विशेष अथवा विशेष विषय के बारे में आवश्यक जानकारी भी प्रदान करता है जिससे कि उस विषय अथवा समस्या को लेकर पाठक एक निरपेक्ष एवं आलोचनात्मक मत बना सके ।आतंकवाद एवं तालिबान जैसे अति संवेदनशील मुद्दों पर शोध पत्र का अपने आप में विशेष महत्व है क्योंकि इससे न केवल वर्तमान विश्व की एक महत्वपूर्ण समस्या के परिदृश्य को समझने में मदद होगी बल्कि इससे संबंधित धार्मिक , सामाजिक , मानवीय एवं राजनीतिक पहलुओं को भी समझा जा सकता है । मेरे शोध पत्र में आतंकवाद विशेष रूप से तालिबान के संदर्भ में सूक्ष्म स्तर पर विवेचना की गई है और उसका महत्व कई स्तरों पर माना जा सकता है।

1. तालिबान के उद्देश्य एवं उसकी प्रकृति का विश्लेषण :

इस शोध के द्वारा हम तालिबान एवं उसके जैसे अन्य आतंकी संगठनों के उद्भव के पीछे के कारण , विचारधारा , कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं । आज यह जानना बेहद ज़रूरी है कि किस प्रकार ये आतंकी संगठन युवाओं को कट्टरता की राह पर धकेलते जा रहे हैं और किस प्रकार अपने शासन को वैध बनाने एवं अपनी वैचारिकता के प्रचार - प्रसार को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं ।

2. मानवाधिकारों का हनन एवं सामाजिक दुर्दशा का अध्ययन :

तालिबान शासन के दौरान किए गए मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का अध्ययन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है । 1990 के दशक के दौरान तालिबान द्वारा विशेषरूप से महिलाओं के अधिकारों एवं लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध किए गए अत्याचारों को संबोधित किया जा सकता है क्योंकि इस शोध के द्वारा पीड़ित समुदायों की विवशता एवं उनके दर्द को दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम भी बना जा सकता है ।

3. विश्व की सुरक्षा एवं शांति के लिए सहयोगी :

इस प्रकार के शोधों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति , नीति निर्धारण एवं वैश्विक सुरक्षा रणनीतियों के निर्माण में भी मदद मिलती है ,क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद आज एक वैश्विक राजनीतिक चुनौती बना हुआ है । यह शोध तालिबान की आर्थिक नीतियों , मादक पदार्थों की तस्करी एवं उसकी इन नीतियों से क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पढ़ने वाले प्रभावों की भी जाँच करता है । तालिबान के उदय विशेष रूप से 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के अधिग्रहण के पश्चात क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है ।

4. बौद्धिक एवं शैक्षणिक विकास में योगदान :

यह विषय अंतरराष्ट्रीय संबंध ,राजनीति विज्ञान ,समाज शास्त्र एवं मानवाधिकार के क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्रों एवं शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है ।

5. समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास :

आतंकवाद की उत्पत्ति एवं उसके पीछे के कारणों तथा इसके प्रसार के तरीकों को जानकर हम इस समस्या के समाधान के लिए एक ठोस रणनीति या मसौदा तैयार कर सकते हैं । हम यह भी समझ सकते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए शिक्षा ,संवाद , वैश्विक सहयोग अति आवश्यक है।

संक्षेप में आतंकवाद एवं तालिबान पर आधारित शोध क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को समझने , इनसे निपटने के लिए प्रभावकारी रणनीतियों के निर्माण एवं एक जटिल तथा समकालीन महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर जानकारी का एक स्रोत है । यह विश्व को एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण दिशा की ओर ले जाने का एक सूक्ष्म प्रयास भी है।

संदर्भ

1. “ Global terrorism index report 2015 “ (PDF) : Institute for economics and peace, November 2015, page number 10
2. “ Global terrorism index 2016 “ (PDF) Institute for economics and peace, 2016, page number 4
3. Holbrook , Donald (2010) “ Using the Quran to justify terrorist violence “ Perspective on Terrorism.



4. एलेक्जेंडर एलेक्जीव - “ संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध “ संता मोनिका सीए : रैण्ड कॉरपोरेशन ,1988
5. ग्राहम ई फ़ुलर - “ अफ़ग़ानिस्तान में इस्लामिक कट्टरवाद : इसकी विशेषता और संभावनाएं “ संता मोनिका सीए , रैंड कॉरपोरेशन 1991
6. माइकिल ग्रिफ़िन - “ बवंडर काटना : अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान आंदोलन “ लंदन , प्लूटो प्रेस 2001
7. पीटर मार्सडेन - “ तालिबान : अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध और धर्म “ लंदन जेड बुक्स लिमिटेड ,2002
8. एम जे गोहरी - “ तालिबान - सत्ता की चढ़ाई “ पाकिस्तान : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2000
9. विलियम मैले - “ अफ़ग़ानिस्तान और तालिबान : कट्टरवाद का पुनर्जन्म “ वॉशिंगटन स्क्वेयर एन वाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस , 2001
10. सैफ़ आर समदी - “ बीसवीं सदी में शिक्षा और अफ़ग़ान समाज “ पेरिस : यूनेस्को , 2001
11. कृष्ण कुमार - “ महिला और नागरिक युद्ध : प्रभाव , संगठन और कार्यवाही “ बॉल्डर , लिने राइजर , 2001